MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise in view of (a) above.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की निजी सचिवों (प्राईवेट सेक्रेटरी) के रूप में नियुक्ति

1010. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ भ्रष्ट अभियंताओं को मंत्रियों के निजी सचिवों और निजी सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये अधिकारी वित्तीय धांधली और राबन के दोषी पाये गये हैं;

(ग) उन अभियंताओं और मंत्रियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ ये अभियंता नियुक्त हैं; और

(घ) उन्हें निजी स्टाफ में नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) से (घ) केन्द्रीय-लोक-निर्माण-विभाग का कोई भी इंजीनियर, वर्तमान मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति, संबंधित मंत्रियों द्वारा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय को इस बारे में कोई भी संदर्भ भेजे बिना ही की जाती है। अतः यदि केन्द्रीय-लोक-निर्माण-विभाग के कोई इंजीनियर मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों के रूप में कार्य कर रहे हों तो उनके बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय विभागों में भ्रष्टाचार के मामले

1011. **श्री रामजी लाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में केन्द्रीय विभागों में "भ्रष्टाचार के हजारों मामलों" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले आठ महीनों के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कब तक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले आठ महीनों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने 461 मामले दर्ज किए हैं जिनमें से 89 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं। 39 मामले नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं और 5 मामले बन्द कर दिए गए हैं। शेष 328 मामले अन्वेषण हेतु लम्बित चल रहे हैं और उनके संबंध में कानून/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) भ्रष्टाचार की रोकथाम करना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति, सरकार ने निवारक सतर्कता, निगरानी तथा सुगारसानी और निवारक दण्डात्मक कार्रवाई संबंधी त्रि-सूत्री रणनीति अपनाई है जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो अपने-अपने संबंधित संगठनों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के संस्थानिक ढांचों को भी सशक्त सुदृढ़ और सुविधा-सम्पन्न बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी नागरिक सुस्थापित कानून के अनुसार, किसी लोक-सेवक द्वारा अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किए जाने और भ्रष्टाचार किए जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया को सक्रिय बनाने हेतु किसी पुलिस स्टेशन अथवा कानून की अदालत में जा सकता है।

सतर्कता आयुक्त के पद को समाप्त करना

1012. **श्री जनेश्वर मिश्र:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1999 के राष्ट्रीय सहारा में "सतर्कता आयुक्त का पद खत्म करने की तैयारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सतर्कता आयुक्त के पद को समाप्त करना चाहती है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

Collection of money by Kendriya Bhandar

1013. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Bhandar is collecting large sums of money from the suppliers it registers and does not pay interest thereon;

(b) if so, how much money has the Kendriya Bhandar collected so far and at what rate from the suppliers and the reasons for sparing some suppliers for not paying the money; and

(c) under which law is the Kendriya Bhandar doing so and what steps Government are taking to ensure the stopping of the illegal pratice forthwith and to refund the entire money to the suppliers with interest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) As per its approved purchase policy, Kendriya Bhandar invites tenders for registration of suppliers wherein tenders are required to deposit earnest money of Rs. 10,000/-. This money is refunded to unsuccessful tenderers after finalisation of the tenders. In case of successful tenderers this money is converted into security deposit and retained by Kendriya Bhandar. Security deposit of Rs. 10,000/- is also levied from manufacturers/authorised distributors of branded products who submit their proposals for registration in Kendriya Bhandar. No interest is paid on the earnest money/security deposit by Kendriya Bhandar.

Security deposit is not insisted upon from public sector undertakings and cooperative societies. Exemptions may also be given in very hard cases as an exception. As on date, an amount of Rs. 91.97 lakhs is lying Kendriya Bhandar as security deposit/earnest money deposit.

(c) According to Kendriya Bhandar, there is a practice to collect earnest money and security deposit against tenders invited/suppliers registered. Earnest money is levied to ensure that tenderers do not withdraw their offers within the tender validity period. This also ensures that only serious bidders participate in the tenders. Security deposit is levied for due performance of the supply contract and is part of the contract mutually agreed upon. Security deposit is refunded to the concerned suppliers on their request if either they themselves or the Kendriya Bhandar decide(s) to discontinue supplies.

Replies to letters of MPs by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

1014. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inordinate delay is taking place in replying to the letters of the Members of Parliament by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of letters pending reply in the Ministry and since when;

(d) whether the Ministry is the nodal Ministry to issue guidelines to other Ministries to answer the letters of M.Ps; and

(e) if so, the reasons for its failing in not replying to letters and by which date will all the pending letters be replied?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND